PAPER- II

OPEN MARKET OPERATIONS

प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व साख-नियन्त्रण के एक साधन के रूप में बैंक-दर का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता था। किन्तु युद्धकाल के पूर्व भी जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इस कार्य के लिए खुले-बाजार की नीति का प्रयोग किया जाने लगा था। सुप्रसिद्ध विद्वान De Kock के अनुसार, "विस्तृत अर्थ में खुले बाजार की नीति का तात्पर्य केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा-बाजार में किसी भी प्रकार की बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय तथा संकीर्ण अर्थ में इनका तात्पर्य केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों- दीर्घकालिन अथवा अल्पकालीन - का क्रय एवं विक्रय है।

खुले बाजार की नीति का सिद्धान्त :-

केन्द्रीय बैंक के साख-नियंत्रण के साधन के रूप में खुले बाजार की नीति का सिद्धान्त यह है कि केन्द्रीय बैंक देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी के लिए मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय अथवा विक्रय करता है। खुले बाजार की नीति द्वारा केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष की मात्रा में परिवर्तन लाकर उनके साख-सृजन की नीति को प्रभावित करता है। इससे ब्याज की दर भी प्रभावित होती है जिसके फलस्वरूप मूल्य, लागत, एवं उत्पादन स्तर प्रभावित होते हैं। अतः खुले बाजार की नीति को नीति साख-नियंत्रण का एक प्रधान

स्वायत्त है। किन्तु बैंक-दर एवं खुले बाजार की नीति में प्रधान अंतर यह है कि जबकि बैंक-दर का साख एवं मुद्रा पर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव पड़ता है, खुले बाजार की नीति साख नियंत्रण का एक अधिक प्रत्यक्ष एवं व्यापक तरीका है बशर्ते कि देश में अल्पकालिन एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए एक सुविकसित मुद्रा बाजार हो।

खुले बाजार की नीति तथा पुनः बट्टा करने के परिणाम प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैं। व्यावसायिक बैंक अथवा बट्टा गृहों की पुनः बट्टा की सुविधा केन्द्रीय बैंक बैंक-दर पर ही प्रदान करता है। इसके परिणाम-स्वरूप बाजार की सूद-दर भी प्रायः बढ़ जाती है जिससे बैंक-मुद्रा का प्रसार रुक जाता है। किन्तु खुले बाजार नीति के अन्तर्गत सूद की दर में वृद्धि किये बगैर ही केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष में वृद्धि या कमी करते हैं।

खुले बाजार की नीति की सफलता की शर्तें:— खुले बाजार की नीति का उद्देश्य केवल बैंक मुद्रा अथवा साख का नियंत्रण करना ही नहीं, अपितु इसका उद्देश्य मूल्य-तल एवं व्यावसायिक क्रियाशीलता को स्थायी बनाना भी होता है। उनत! इस कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्नांकित शर्तें अनिवार्य हैं:—

(1.) खुली बाजार-नीति के परिणामस्वरूप चलन में मुद्रा की मात्रा एवं व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष में उसी अनुपात में अंतर होना चाहिए जिस अनुपात में केंद्रीय बैंक की खुली बाजार नीति का उद्देश्य हो।

(2.) व्यावसायिक बैंक अपने नकद कोष में परिवर्तन के अनुरूप ही अपने ऋण तथा विनियोग में परिवर्तन करने के लिए तैयार हों।

(3) बैंक मुद्रा की माँग में लाभ के आधार एवं ब्याज की दर में परिवर्तन के अनुरूप ही परिवर्तन होना चाहिए

(4) प्रतिभूतियों की माँग तथा पूर्ति सदा वर्तमान नहीं रहने से केंद्रीय बैंक की खुली बाजार की नीति सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती

क्रमशः